

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

**खादी उद्योग में रोजगार की संभावनाएं, चुनौतियाँ एवं समस्याओं का अध्ययन**

कीर्ति श्रीवास, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग

दीपा देवांगन, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग

शासकीय काव्योपाध्याय, हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE**Corresponding Authors**

कीर्ति श्रीवास, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग

दीपा देवांगन, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग

शासकीय काव्योपाध्याय, हीरालाल महाविद्यालय,
अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/02/2022

Revised on : -----

Accepted on : 08/02/2022

Plagiarism : 01% on 01/02/2022

**Plagiarism Checker X Originality Report**

Similarity Found: 1%

Date: Tuesday, February 01, 2022

Statistics: 16 words Plagiarized / 2544 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

[kknh m]ksx esa jkstkj dh laHkkouk,a] pqukSfr;KW ,oa leL;kvksa dk vj;:u M, dhfrZ Jhokl M, nhik nsokaxu lgc;dk;/kid vfrfFk lgc-ck;/kid 'kkldh; dkO;ksik;/k; 'kkldh; dkO;ksik;/k; ghjkyky egkfojky; ghjkyky egkfojky; vHkuiqj vHkuiqj 'kks/k lkjka'k fdll Hkh ns'k ds vkfFkZd fodkl dk vfuok;Z dkjd gS] :gh dkj.k gS fd dsaae ljdkj Hkh jkstkj ds u, volj iSnk djus ij lcls vf/kd cy ns jgh gSA -f'k ds ckn vkSj xSj -f'k [ks= ds varxZr e;/e ,oa y?kq rFkk dqVhj m]ksxksa dh bdkbZ;ka gh xkao esa cM+s iSekus ij jkstkj miyC/k dkj jgh gSA dqVhj m]ksx dh bdkb;ksa esa lcls cM+k Hkkx [kknh bdkb;ksa dk gS] q/kkuea=h Jh ujsaae

शोध सार

रोजगार किसी भी देश के आर्थिक विकास का अनिवार्य कारक है, यही कारण है कि केंद्र सरकार भी रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर सबसे अधिक बल दे रही है। कृषि के बाद और गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों की इकाइयां ही गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रही है। कुटीर उद्योग की इकाइयों में सबसे बड़ा भाग खादी इकाइयों का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2014 को अपने रेडियो अभिभाषण मन की बात में लोगों से खादी अधिक से अधिक उपयोग करने का निवेदन किया था और अपनी मंशा जाहिर की थी, वह चाहते हैं कि खादी का उपयोग बढ़े, ताकि देश में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। 'प्रस्तुत शोध पत्र में खादी उद्योग में संभावित रोजगार की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ व समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।'

मुख्य शब्द

रोजगार, कुटीर उद्योग, अर्थिक विकास, खादी.

प्रस्तावना

गांधीजी ने खादी के संदर्भ में कहा था "खादी की अवधारणा और भी बड़े उद्देश्य के साथ विकसित की गई थी और वह यह है अपने गांव को भूख से मुक्त करना" इस उक्ति में गांधीजी का ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में खादी के योगदान का सपना झलकता है। खादी रोजगार जुटाकर तथा स्वदेशी का गौरव जागृत करके भारत के गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाकर और सूत कातकर, स्वाधीनता की जंग के साथ ही स्वालंबन की जंग भी जीती। आज भी खादी के रूप में महात्मा

गांधी का संदेश हमारे बीच मौजूद है। बदलते परिवेश में भी खादी की धाक बढ़ती जा रही है, यह अलग बात है कि खादी का स्वरूप बदला है। गांधी जी ने कहा था कि – खादी एक विचार है, खादी एक संदेश है, खादी एक दर्शन है। इसी दर्शन के दम पर आज खादी के जरिए रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां परंपरागत कौशल एवं उद्योगों का अथाह भंडार है, खादी जैसे उद्योग के विकास एवं उपयोग की काफी संभावनाएं हैं। खादी की पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के, परंपरागत कौशल के अनुवांशिक ज्ञान की सहायता से आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने और उनके विकास की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं।

उद्देश्य

1. खादी कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन।
2. खादी के लिए संचालित योजनाओं व जीवन स्तर में सुधार का अध्ययन।
3. कोविड – 19 के समय खादी व ग्रामोद्योग द्वारा कारोबार की स्थिति का अध्ययन।

शोध प्रविधि

इस शोधपत्र में तथ्यों के स्पष्टीकरण, विश्लेषण और निष्कर्षों के प्रतिपादन में द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है। अध्ययन पश्चात् इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य से लेकर विभिन्न शोध प्रविधियों का उपयोग कर सार्थक व बहुपयोगी निष्कर्ष प्राप्त करना है।

साहित्य पुनरावलोकन

1. सत्यनारायण, कस्तूरबा ग्राम- इंदौर आलेख उद्यमिता पत्रिका (अक्टूबर 2007)
विषय: “खादी भारतीय समाज की आत्मा”

हाथ से कता धागा और हाथ से बुना कपड़ा ही खादी है। यह देश के हर बेकार हाथ को काम देने की गारंटी देता है। खादी सर्वोत्तम है पहनने में, ओढ़ने में, बिछाने में और घर सजाने में। वस्तुतः खादी एक आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा उपकरण है खादी सामाजिक एकरूपता और सद्भाव सबसे बड़ी संभावना है।

2. देवेश चंद्र, कानपुर आलेख उद्यमिता पत्रिका (अक्टूबर 2007)
विषय: “खादी ग्राम उद्योग संवर्धन महासंघ”

उन्ही वस्त्रों को खादी माना जाता है जिनकी बुनाई किसी संस्था के द्वारा करवाई जाती है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग का प्रमाण पत्र प्राप्त होता हो। ऐसे किसी बुनकर के द्वारा तैयार वस्तु को खादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता जो भले ही हाथ से कते धागे से बुनाई करता हो।

3. वैश्य एम. सी., आलेख उद्यमिता पत्रिका। (अक्टूबर 2007)
विषय: “महात्मा गांधी के आर्थिक विचार”

चरखा बेरोजगारी समाप्त करने की कुंजी होने के अतिरिक्त खादी के उत्पादन को बढ़ाने का भी एक अच्छा साधन था।

4. शुक्ला दिनेश, इलाहाबाद उद्यमिता पत्रिका (अक्टूबर 2007)
विषय: “खादी संबंधित प्रमुख शिल्प”

खादी उत्पादन में हाथ से कते तथा बने वस्तुओं के अलावा गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण शामिल है। सामान्यतया खादी के समस्त उत्पाद सुविधाजनक सस्ते तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

5. अजबे प्रभाकर, कस्तूरबा ग्राम-इंदौर आलेख पत्रिका उद्यमिता पत्रिका (अक्टूबर 2007)
विषय: “खादी में अनुसंधान एवं विकास”

जब तक संपूर्ण भारत पूर्ण रूप से सुशिक्षित नहीं हो जाता और कृषि पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ग्रामीण रोजगार के लिए खादी और ग्रामोद्योग के सिवाय इसकी कोई गारंटी नहीं है। बदलते वक्त के साथ खादी उच्च वर्ग की पसंद बन गया है।

खादी के क्षेत्र में सरकार के प्रयास

खादी उद्योग सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयासरत हैं। सबसे पहला प्रयास इस दिशा में सन् 1956 में हुआ था। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना हुई थी। अगले ही वर्ष 1957 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को इस उद्योग को आयोग के तहत ला दिया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह स्वतंत्र भारत का खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में पहला अधिकारिक एवं सरकारी प्रयास था, जो आज भी संचालित है। हालांकि समय और जरूरत के अनुरूप सन् 1987 एवं 2006 में इसमें संशोधन भी किए जा चुके हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के तीन उद्देश्य निर्धारित हैं, जिनमें प्रथम उद्देश्य खादी उद्योगों को कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करना है, दूसरा उद्देश्य ऐसा उत्पाद तैयार करवाना जिनके विक्रय के लिए बाजार में संभावनाएं हैं और तीसरा उद्देश्य खादी ग्राम उद्योग के जरिए अधिकाधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाना है। आयोग ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रशासनिक व आर्थिक रूप से संचालन करता है। अब क्योंकि भारतीय लोकतंत्र संघीय ढांचे पर आधारित है लिहाजा इस कुटीर खादी ग्राम उद्योग के प्रोत्साहन की दिशा में भी केंद्र व राज्य स्तर पर योजनाओं कार्यक्रमों आदि का होता है। केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ब्याज अनुभूति पात्रता प्रमाण पत्र योजना आदि प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सभी तरह के ग्राम उद्योग और कुटीर खादी ग्राम उद्योग भी आते हैं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्थापित करवाना है। इसके तहत व्यक्ति को परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत पहले स्वयं निवेश करना होता है, इसके बाद शेष 90 प्रतिशत की सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत बैंकों में से किसी द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रमुख रूप से संचालन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ब्याज अनुमति पात्रता प्रमाण पत्र योजना की बात करें तो यह समग्र खादी उद्योग के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। इसका आरंभ सन् 1988 में तब किया गया जब खादी ग्राम उद्योग के लिए निर्धारित बजट प्राप्ति के बीच अंतर बढ़ने लगा इसके तहत बैंक द्वारा व्यक्ति को उसकी कार्यात्मक राशि की पूर्ति हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह खादी से संबंधित उद्योगों के लिए ही प्रदान करती है व खादी निर्माण करने वाले व्यक्तियों को ही प्रदान करते हैं। खादी ग्राम उद्योग से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी खादी को लेकर तमाम योजनाएं व कार्यक्रम संचालित है। देश के लगभग हर राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मौजूद है जिसके तहत राज्य के खादी ग्राम उद्योग से संबंधित योजनाओं का संचालन हो रहा है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कोविड-19 महामारी के बावजूद वित्त वर्ष 2021 में कारोबार की स्थिति

कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से प्रभावित साल 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार किया है वर्ष 2020 में आयोग ने 95740.74 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार किया। पिछले वर्ष 2019 में 88887 करोड़ रुपए के कारोबार में इस साल करीब 7.71 प्रतिशत की वृद्धि आई है। 2020 में खादी आयोग का रिकॉर्ड प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पिछले साल 25 मार्च को पूरे देश में लॉक डाउन की घोषणा के चलते उत्पादन गतिविधियां 3 महीने से अधिक समय तक निलंबित रही थी, इस अवधि के दौरान सभी खाद्य उत्पादन इकाइयां और बिक्री आउटलेट बंद रहे, जिससे उत्पादन और बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि खादी उद्योग तेजी से आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर लोकल के आह्वान पर तेजी से काम किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनोखे मार्केटिंग आईडियाज के केवीआईसी की उत्पादन श्रृंखला को और भी विविधता प्रदान की स्थानीय उत्पादन को बढ़ाया और खादी के क्रमिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2015-16 की तुलना में 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान कुल बिक्री में 128.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ई-पोर्टल खादिम फुटवियर, खादी प्राकृतिक और खादी हैंड सैनिटाइजर आदि का शुभारंभ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी इकाइयों की रिकॉर्ड संख्या की स्थापना, स्फूर्ति कलस्टर, स्वदेशी के लिए सरकार की पहल और खादी आयोग का अर्धसैनिक बलों के सामग्री की आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक समझौते से, महामारी के इस दौर में केवीआईसी के कारोबार में वृद्धि हुई है। ग्राम उद्योग ने 2019 में 65393.0 करोड़ रुपए के खाद्य उत्पादन की तुलना में 2020 में 70329.67 रुपये का उत्पादन किया। इसी तरह से वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 92214.03 करोड़ रुपए का था, 2020-21 में खादी बिक्री 3527.71 करोड़ रुपए की हुई और पिछले वर्ष में यह बिक्री 4211.6 करोड़ रुपए की रही।

खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक प्रदर्शन

S.NO.	Particulars	2017-18	2018-19	% Increase
1	PRODUCTION			
A.	Khadi	1465.21	1765.51	20.5
B.	Polyvastra	159.67	191.7	20.06
c.	Solarvastra	1.78	6.09	242.13
	Total(khadi,polyvastra & solarvastra)	1626.66	1963.3	20.7
D.	village Industries	46454.75	56167.04	20.91
	Total-I	40801.41	58130.34	20.9
II.	SALES			
A.	khadi	2249.18	2854.19	26.9
B.	polyvastra	259.32	355.47	37.08
C.	solarvastra	1.71	5.47	219.88
	Total (khadi, Polyvastra & Solarvastra)	2510.21	3215.13	28.08
D.	Village Industries	56672.22	71076.96	25.42
	Total-II	59182.43	74292.09	25.53
III.	EMPLOYEMENT			
A.	Khadi	4.34	4.6	5.99
B.	Polyvastra	0.29	0.36	3.45
C.	Solavastra	0.02	0.06	200
	Total (khadi, Polyvastra & Solarvastra)	4.65	4.96	6.67
D.	Village Industries	135.71	142.03	4.66
	Total-III	140.36	14.99	4.72
IV.	EARNINGS			
A.	khadi	761.83	916.31	20.28
B.	Polyvastra	81.61	98.06	20.07
C.	Solavastra	0.91	3.01	230.77
	Total (khadi, Polyvastra & Solarvastra)	844.41	1017.38	20.48
D.	Village Industries	21549.79	26103.82	21.13
	Total-IV	22394.2	27121.2	21.11

(Source: Khadi & villiage industries commission Annual report 2018-19)

उपरोक्त सारणी में 2 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में उत्पादन में (खादी, पॉलीवस्त्र, सोलर वस्त्र) बिक्री, रोजगार, अर्जन को बताया गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि को दर्शाता है और भविष्य में भी इस उद्योग की अपार संभावनाओं को प्रस्तुत करता है।

समस्याएं

1. खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छोटी और परंपरागत मशीनें ही उपलब्ध कराई जाती हैं जबकि व्यक्ति कम समय में अधिक उत्पादन करना चाहता है, इसके लिए आधुनिक मशीनरी की सर्वथा कमी ही दिखाई पड़ती है। आधुनिक मशीनी युग में जहां कम कीमत पर अच्छी वस्तुओं का निर्माण संभव हो गया है ऐसी परिस्थिति में इस उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा कर बाजार में अपना वर्चस्व बनाए रखना असंभव हो गया है। अतः प्रतियोगिता में असफलता इस उद्योग की लोकप्रियता में कमी का मुख्य कारण है।
2. खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधी कठिनाइयों का सामना कारीगरों को करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा का स्तर ऊपर उठते जा रहा है, इस योजना का औचित्य खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा इतनी छोटी इकाइयां स्थापित नहीं करना चाहता है।
3. खादी ग्रामोद्योग की असफलताओं में बाजार की समस्या भी उल्लेखित है। कारीगर यदि सामान बना भी लेते हैं तो बाजार की कमी के कारण उनका तुरंत विक्रय नहीं हो पाता है और गरीब कारीगरों के पास इतना अधिक साधन नहीं होता है कि सामान बनाकर उसका स्टॉक रख सकें।
4. खादी उत्पादों के संगठन नहीं है, अथवा अगर है तो कमजोर है, इन्हें कई जगहों पर हानि उठानी पड़ती है।
5. उद्योग प्रारंभ करने हेतु विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करनी होती है एवं अनेक प्रमाण पत्र भरने होते हैं। ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति इस पेचीदा योजना की अपेक्षा, मजदूरी करना या साहूकारों से ऋण लेना बेहतर समझते हैं।
6. खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुई है, किंतु इतने वर्षों बाद भी विज्ञापन एवं प्रचार की कमी के कारण जिले का प्रत्येक ग्राम इस योजना से परिचित नहीं है। विभाग द्वारा जो अनुदान की व्यवस्था की गई है वह भी लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
7. इस विभाग द्वारा जहां बहुत से उद्योगों पर अनुदान की व्यवस्था ही नहीं की गई है, वहीं जिन उद्योगों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है, वह भी बहुत कम है।
8. खादी उत्पादन के लिए कच्चे माल माल की समस्या बनी होती है, क्योंकि इसके लिए कपास का उत्पादन कम मात्रा में होता है।

सुझाव

1. खादी ग्रामोद्योग के तहत जो अपर्याप्त राशि हितग्राहियों को आवंटन किया जाता है उनमें वृद्धि इस विभाग की सफलता के प्रथम सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत आज भी निम्न है। यह अशिक्षित व्यक्ति विभाग द्वारा चाही गई औपचारिकताओं को बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। अतः विभाग को चाहिए कि यह ऋण प्रदान की अपनी योजना को इतना सरल बनाए ताकि अनपढ़ ग्रामीण भी इसके लिए आकर्षित हो।
3. इसकी प्रमुख समस्याओं में बाजार की समस्या भी उल्लेखित है, इन कारीगरों को अपने निर्मित वस्तु को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः विभाग द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाना अति आवश्यक है। विभाग को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर बाजार का निर्माण करें जिससे वस्तु निर्माण के पश्चात् ही तुरंत बेची जा सकें।
4. उद्यमी अपने कार्य में सफल हो सकता है, जब वह अपने उद्यम के बारे में पूर्ण रूप से जानकार हो। खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा ऋण प्रदान करने की पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे हितग्राही को उद्योग की स्थापना से लेकर वस्तु निर्मित होने तक की समस्याओं के बारे में जानकारी दिया जाए।

5. हितग्राहियों की समस्या में कच्चे माल की समस्या उद्योग की असफलता में एक महत्वपूर्ण कारण साबित होती है। अतः विभाग द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर उपलब्धता का अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता का प्रबंध किया जाना चाहिए।
6. हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र गांव के मध्य में होना चाहिए, ताकि खासकर महिलाओं को अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर प्रशिक्षण के लिए ना जाना पड़े व प्रशिक्षण व्यवहारिक होना चाहिए, जो उनके काम में आ रही कठिनाइयों का आसानी से समाधान प्रदान कर सके।

निष्कर्ष

यह बात हम सब प्रमाण से कह सकते हैं कि खादी के उत्पादन में या इसके विक्रय में जो समस्याएं आती हैं उनको सरकार के समक्ष रखकर, बहुत सी समस्याओं को दूर कर, ग्रामीण जन अपनी रोजगार के उपलब्ध अवसरों का रचनात्मक रूप से प्रयोग कर जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। अपने विकास के साथ अपने परिवार को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान कर वे देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं, इसके लिए सरकार संभवतः पूर्ण रूप से प्रयासरत् है। खादी ग्राम उद्योग में चलाए जा रहे कार्यक्रम निःसंदेह सराहनीय है जो ग्रामीण जन के विकास में हर संभव प्रयासरत् हैं ताकि रोजगार के नये व अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

संदर्भ सूची

1. कुरुक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर 2015
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट।
3. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट
4. सत्य के प्रयोग और आत्मकथा पुस्तक से साभार।
5. विभिन्न समाचार पत्रों समय-समय पर प्रकाशित।
6. जिला प्रशासन खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।
7. डीसी, भारत में ग्रामीण विकास, सुधा कंप्यूटर्स जयपुर।
8. माथुर बी गंगाधर, ग्रामीण विकास के लिए संभावित प्रयास, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
